Research Unit
Press Information Bureau
Government of India

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025: हितधारक जुड़ाव के माध्यम से सुधार

परिचय

वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और शासन में कमियों को दूर करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। इन संशोधनों का उद्देश्य अधिक स्पष्टता प्रदान करना, समावेशिता सुनिश्चित करना और वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग के लिए प्रशासनिक ढांचे को बेहतर करना है।

8 अगस्त, 2024 को वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोकसभा में दो विधेयक, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 पेश किए गए थे।

मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 का प्राथमिक उद्देश्य मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 को निरस्त करना है, जो एक औपनिवेशिक युग का कानून है और आधुनिक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए पुराना और अपर्याप्त हो गया है। निरसन का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और

प्रबंधन में एकरूपता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, इस प्रकार इस निरर्थक कानून के निरंतर अस्तित्व के कारण होने वाली विसंगतियों और अस्पष्टताओं को समाप्त करना है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में मुद्दों और चुनौतियों का निवारण किया जा सके। संशोधन विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना चाहता है। इसका उद्देश्य है:

1. पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने जैसे परिवर्तनों को पेश करके वक्फ बोर्डों की दक्षता में वृद्धि करना
2. वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करना
3. पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार
4. वक्फ अभिलेखों के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना।

TIMELINE OF WAQF AMENDMENT BILL 2025

AUGUST 8, 2024

- The Waqf (Amendment) Bill, 2024 was introduced
- Hon'ble Minister-in-charge of the Bill proposed constituting a Joint Committee of both the Houses and referring the Bill to it.

AUGUST 9, 2024

- The Bill was referred to a Joint Committee with the mandate to examine the Bill and make a report for the Parliament.
- Committee decided to call memoranda to obtain the views from public in general and experts/stakeholders on the provisions of the aforesaid Bill.

AUGUST 22, 2024

The first sitting took place on August 22, 2024 and the key organizations/ stakeholders consulted

AUGUST 29, 2024

A press communiqué inviting memoranda was issued in national and regional newspapers through the Central Bureau of Communication.

AUGUST 2024- JANUARY 2025

Joint Committee conducted extensive study visits to various cities across multiple cities in India

JANUARY 27, 2025

Joint Committee completed Clause by Clause consideration of all Clauses of the Bill at their 37th sitting

JANUARY 29, 2025

Adoption of the draft report and Chairperson was authorized to present it on their behalf at the 38th sitting held on January 29, 2025

JANUARY 31, 2025

Joint Committee submitted its report to the Hon'ble Speaker of Lok Sabha on 31.01.2025

FEBRUARY 13, 2025

Joint Committee submitted its report to the Hon'ble Speaker of Lok Sabha on 31.01.2025

इस विधेयक के विशिष्ट पहलू:

1. **09** अगस्त**, 2024** को संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाए गए अलग-अलग प्रस्तावों के माध्यम से उक्त विधेयक को विधेयक की जांच करने और रिपोर्ट बनाने के जनादेश के साथ एक संयुक्त समिति को भेजा गया था। संयुक्त समिति में लोक सभा के **21** सदस्य और राज्य सभा के **10** सदस्य शामिल थे।
2. विधेयक के महत्व और इसके व्यापक निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने विधेयक के प्रावधानों पर आम जनता और विशेषज्ञों/हितधारकों और विशेष रूप से अन्य संबंधित संगठनों से विचार प्राप्त करने के लिए ज्ञापन आमंत्रित करने का निर्णय लिया था ।
3. पहली बैठक **22** अगस्त**, 2024** को हुई और बैठकों के दौरान जिन प्रमुख संगठनों/हितधारकों से परामर्श किया गया, वे थे:

संख्या	प्रमुख संगठन/हितधारक
i.	ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, मुंबई;
ii.	नागरिक अधिकारों के भारतीय मुस्लिम (आईएमसीआर), नई दिल्ली

iii.	मुत्ताहेदा मजलिस-ए-उलेमा, जम्मू-कश्मीर (मीरवाइज उमर फारूक)
iv.	जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया
v.	अंजुमन ए शितेवाली दाऊदी बोहरा समुदाय
vi.	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना
vii.	ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज, दिल्ली
viii.	ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी), दिल्ली
ix.	अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीं परिषद (एआईएसएससी), अजमेर
x.	मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली -
xi.	मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह - डॉ. शालिनी अली, राष्ट्रीय संयोजक
xii.	जमीयत उलमा-ए-हिंद, दिल्ली
xiii.	शिया मुस्लिम धर्मगुरु और बौद्धिक समूह
xiv.	दारूल उलूम देवबंद

1. संयुक्त संसदीय समिति ने छत्तीस बैठकें आयोजित कीं, जिनमें उन्होंने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राज्य वक्फ बोर्डों और विशेषज्ञों/हितधारकों के प्रतिनिधियों/सुझावों को सुना। समिति को भौतिक और डिजिटल दोनों माध्यमों से कुल 97,27,772 ज्ञापन प्राप्त हुए।

2. वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 की व्यापक समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए, संयुक्त समिति ने भारत के विभिन्न शहरों में व्यापक अध्ययन दौरे किए।

   - **26.09.2024** से **01.10.2024:** मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु
   - **09.11.2024** से **11.11.2024:** गुवाहाटी, भुवनेश्वर
   - **18.01.2025** से **21.01.2025:** पटना, कोलकाता और लखनऊ

3. समिति ने इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जिसमें **284** हितधारकों, **25** राज्य वक्फ बोर्डों, **15** राज्य सरकारों, **5** अल्पसंख्यक आयोग और **20** मंत्रियों/सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों के साथ बातचीत शामिल थी। इन यात्राओं ने समिति के सदस्यों को हितधारकों के साथ जुड़ने, जमीनी वास्तविकताओं की जांच करने और क्षेत्र-विशिष्ट जानकारी एकत्र करने की अनुमति दी।

4. वक्फ (संशोधन) विधेयक में 44 खंड हैं और वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूएबी) ने 19 खंडों में परिवर्तन की सिफारिश की है।

5. संयुक्त समिति ने 31 जनवरी 2025 को लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट 13 फरवरी 2025 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी गई।

प्रस्तुत सिफारिशों का एक उदाहरण:

अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम महाज, उनके उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

1. एक अपीलीय प्रणाली की शुरूआत
2. वक्फ अभिलेखों का बेहतर प्रबंधन
3. अतिक्रमण और दुरुपयोग के लिए सख्त दंड
4. अनियमितताओं में शामिल बोर्ड के सदस्यों की अयोग्यता
5. वक्फ संपत्ति राजस्व का उचित उपयोग
6. निष्पक्ष जांच के लिए वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को सशक्त बनाना

समाहार

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट वक्फ संपत्तियों के संतुलित, पारदर्शी और कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। व्यापक परामर्श, अध्ययन दौरों और विचार-विमर्श के माध्यम से,

समिति ने विधायी ढांचे को मजबूत करते हुए हितधारकों द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं को दूर करने की मांग की है। विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य एक अधिक समावेशी और जवाबदेह प्रणाली बनाना है जो समाज की उभरती जरूरतों के अनुरूप हो।

Santosh Kumar/ Ritu Kataria/ Kritika Rane